



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937

No. 36]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/MAGHA 7, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

विषय : चीन जन. गण., दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

सं. 14/29/2015-डीजीएडी.-मै. इंडोरामा इंडस्ट्रीज लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण., दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से 150 डेनियर सहित और उस तक के सभी डेनियरों और सभी लस्टरों (जैसे चमकीले, सेमीडल और डल) परंतु जिसमें रंगीन यार्न शामिल नहीं हैं, के बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद '150 डेनियर सहित और उस तक के सभी डेनियरों परंतु जिसमें रंगीन यार्न शामिल नहीं हैं, के इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न' है। इन फिलामेंट यार्नों को आम तौर पर स्पेनडेक्स या इलास्टेन कहा जाता है। इन यार्नों को बोलचाल की भाषा में 'लाइक्रा' भी कहा जाता है यद्यपि यह एक विशिष्ट ब्रांड नाम है। इन्हें तकनीकी भाषा में 'साफ्ट' या लचीले खंडों से बने हुए सेगमेंटेड पालीयूरेथेन कहा जाता है जिन्हें 'कठोर' या ठोस खंडों से आपस में जोड़ा गया है। इससे फाइबर को उसकी अंतर्निर्मित टिकाऊ इलास्टिसिटी मिलती है। यह एक इलास्टोमेरिक

फाइबर होता है जिसका प्रयोग व्यापक रूप से स्ट्रेच परिधानों में सूक्ष्म संघटक के रूप में होता है ताकि उसे रिकवरी के साथ स्ट्रेच दिया जा सके।

3. स्पेनडेक्स यार्न को प्रयोग मुख्यतः ऐसे परिधान बनाने में किया जाता है जिनमें काफी आराम और फिट होने की जरूरत होती है। इसलिए इनका प्रयोग हौजरी, स्विमसूट, एअरोबिक या व्यायाम परिधान, स्की पैंटों, गोल्फ जैकेटों, डिस्पोजेबल डायपर, वेएस्ट बैंडों, ब्रा स्ट्रेप्स, ब्रा साइड पैन्लों, ब्रा कपों आदि के विनिर्माण में किया जाता है। स्पेनडेक्स फेब्रिक्स का प्रयोग कम्प्रेसन परिधानों में भी किया जाता है जैसे सर्जिकल होज, सपोर्ट होज, बाइसिकल पैंट्स, फाउंडेशन परिधान आदि।

4. संबद्ध वस्तु को डेनियरों के अनुसार वर्णित किया जाता है और आम तौर पर 10-1680 डेनियरों की रेंज में बेचा जाता है। संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्ष 5404 11 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तु का आयात टैरिफ शीर्ष 5402 44 00 और 5402 69 90 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

5. विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न, 150 डेनियर सहित और उस तक के सभी डेनियर, परंतु जिसमें रंगीन यार्न शामिल नहीं हैं।”

समान वस्तु

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात की जारी संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देशों से निर्यात की गई और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के ‘समान वस्तु’ माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मै. इंडोरामा इंडस्ट्रीज लि. द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता या उसके किसी संबंधित पक्षकार ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। चूंकि याचिकाकर्ताका उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में ‘एक प्रमुख हिस्सा’ बनता है, इसलिए याचिकाकर्ता योग्यता को पूरा करता है और नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

शामिल देश

8. वर्तमान जांच चीन जन. गण., दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। आवेदक ने भारत में उत्पादन

लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ के साथ विधिवत रूप से समायोजित करके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

10. इसके अलावा आवेदक ने कोरिया, ताइवान और वियतनाम के संबंध में भी इस आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है कि वे उक्त देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य और न ही कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम रहे थे। इसके अलावा, ऐसी सूचना सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया इस जाँच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्य के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

11. आवेदक ने आईबीआईएस द्वारा प्रकाशित आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। कमीशन, समुद्री भाड़े, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमा, वैट समायोजन और बैंक प्रभारों के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। जाँच की प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से सौदावार आयात आकड़ों का भी विश्लेषण करेंगे।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देशों के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

13. आवेदक ने दावा किया है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। आयातों के कारण क्षति अवधि के दौरान घरेलू कीमतों का ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में लाभ, नियोजित पूंजी पर आया और नकद लाभों जैसे मापदंडों के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटे, नकद घाटे और निवेशों पर ऋणात्मक आय उठानी पड़ रही है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

14. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जांच अवधि

15. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक (12 महीने) की है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2012 से मार्च 2013, अप्रैल 2013 से मार्च 2014, अप्रैल 2014 से मार्च 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) के आकड़ों पर विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना होगा।

समय-सीमा

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जाएं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि उसके किसी भाग के संबंध में 'गोपनीयता' का दावा किया जाता है तो प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित हो।

21. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां दो (2) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

22. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि

ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

26. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2016

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Elastomeric Filament Yarn from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam

F. No. 14/29/2015-DGAD.—M/s Indorama Industries Ltd (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers up to and including 150 Deniers and all lustres (like bright, semi dull and dull) but not including coloured yarns” (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam (hereinafter also referred to as the subject countries).

Product under consideration

- The product under consideration in the present application is “Elastomeric Filament Yarn of all deniers upto and including 150 Deniers, excluding coloured yarns”. These filament yarns are also commonly referred to as Spandex or Elastane. These yarns are also referred to as “Lycra” in the market even though it is a specific brand name. These are described in technical terms as segmented polyurethane composed of “soft” or flexible, segments bonded together with “hard” or rigid segments. This gives the fibre its built-in lasting elasticity. It is an elastomeric fibre used widely as the minor component in stretch garments to provide stretch with recovery.
- Spandex yarn is mainly used to make such garments that require great comfort and fit. As such, they find applications in manufacturing of hosiery, swimsuits, aerobic or exercise wear, ski pants, golf jackets, disposable diaper, waist bands, bra straps, bra side panels, bra cups etc. Spandex fabrics are also used to make compression garments, such as surgical hose, support hose, bicycle pants, foundation garments etc.

4. The subject goods are described in terms of the deniers and are sold generally in the range of 10 - 1680 deniers. The subject goods are classified under chapter heading 5404 11 00. However, it has been claimed by the petitioner, the subject goods are also being imported under tariff headings 5402 44 00 and 5402 69 90. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

5. The Product under Consideration is defined as follows:

“Elastomeric Filament Yarn of all deniers upto and including 150 Deniers, excluding coloured yarns”.

Like Article

6. The petitioner submitted that subject goods produced by the petitioner companies and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. Elastomeric Filament Yarn produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

7. The Application has been filed by M/s Indorama Industries Ltd., as domestic industry of the product under consideration. According to the Petitioner, they are the sole producers of the subject goods in India. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject countries. Since the production of the petitioner accounts for “a major proportion” in the total production of the product under consideration in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

Countries involved

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam.

Normal Value

9. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. The applicant has determined the normal value based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.
10. Further, the applicant has also constructed the normal values in respect of Korea, Taiwan and Vietnam on the grounds that they were neither able to get any documentary evidence nor reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in the said countries. Further, such information is also not available in public domain. The Authority has *prima-facie* considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

Export Price

11. The applicant has determined the export price on the basis of data published by IBIS. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, VAT adjustment and bank charges. During the course of investigation, the Authority will also analyse transaction-wise import data from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S).

Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

13. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports. The demand for the product under consideration has increased over the injury period and subject imports have increased in absolute terms. The imports are undercutting the domestic prices. The imports have suppressed/depressed the domestic prices over the injury period. With regard to consequent impact of the

imports on the domestic industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments. There is sufficient prima facie evidence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

14. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st October 2014 to 30th September 2015 (12 months). However, the injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e. April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014, April 2014 to March-2015 and POI.

Submission of Information

16. The exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Department of Commerce,
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.

21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

22. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the

information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority